>

Title: Resolution regarding special economic development package for the eastern districts of the state of Uttar Pradesh.

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं-

> " कि उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी जिलों, जिन्हें पूर्वांचल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन पर विचार करते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए घोषित पैकेज की तर्ज पर इस क्षेत्र के लिए भी विशेष आर्थिक विकास पैकेज तैयार करने तथा कार्यान्वित करने के लिए तुंत कदम उठाए। "

महोदय, आज आपने हमें इस मुद्दे को उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मेरा उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और इसकी जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा है। यह प्रदेश पहले पांच हिस्सों में था। हमने अपना एक हिस्सा उत्तराखंड अलग कर दिया और अब हमारे पास चार हिस्से हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य, पूर्वांचल और बुंदेलखंड। मेरा पूर्वांचल, जहां की मैं निवासी हूं, वहां के कई माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारा क्षेत्र शायद उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ है। यह आज से नहीं, बहुत सालों से पिछड़ा हुआ है। जब स्वतंत्रता का आन्दोलन शुरू हुआ था तो पूर्वांचल ने ही सबसे पहले आवाज उठायी थी। गाजीपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में हम सब लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठायी।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): आप इलाहाबाद को भूल गयीं। इलाहाबाद तो केंद्र बिन्दु था।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, you can speak on whatever points she has forgotten to mention when your turn comes to speak on this issue in the House.

...(*Interruptions*)

राजकुमारी रत्ना सिंह : महोदय, हमारे पूरे पूर्वांचल ने अंग्रेजों की खिलाफत की। सबसे पहले अंग्रेजों ने हमें पिछड़ा किया। उसके बाद जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने पूर्वांचल के पिछड़ेपन को देखकर वर्ष 1962 में एक कमेटी गठित की, कि पूर्वांचल के लिए कुछ किया जाए। आज मैं फिर से यह विषय उठाना चाहती हूं कि पूर्वांचल की तरफ केंद्र सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाहिए। केंद्र सरकार को पूर्वांचल के निवासियों के लिए बहुत कुछ करना है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्वांचल को और पिछड़ा कर रही है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please do not disturb her.

...(*Interruptions*)

राजकुमारी रत्ना सिंह : महोदय, 20 साल से जब से हम लोगों का राज वहां नहीं रहा, तब से पूर्वांचल धीरे-धीरे पिछड़ता जा रहा है। ...(व्यवधान) 20 साल से पूर्वांचल और पिछड़ता जा रहा है। ...(व्यवधान) मैं पूर्वांचल के लोगों के आक्रोश की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं। हिन्दुस्तान के 7 फीसदी लोग पूर्वांचल में रहते हैं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Sir, my request is that if the hon. Members from the other side want to counter any point that is being said by the hon. Member, then they can do so when they themselves get a chance to speak. But let her not be interrupted like this in the House. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please keep quiet.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: This is exactly what I was suggesting just now. I will allow you whenever your turn comes, and you can refute the points made by the hon. Member. Please do not disturb her right now.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please continue your speech.

...(*Interruptions*)

राजकुमारी रत्ना सिंह : महोदय, पूर्वांचल में भारत के 7 प्रतिशत लोग रहते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इन 7 प्रतिशत लोगों में सबसे ज्यादा पिछड़ापन है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। सबसे पहले हम हैल्थ और एजुकेशन पर आते हैं। पूर्वांचल में सबसे कम चाहे एलोपैथिक हॉस्पीटल हों या मैटरनिटी एवं चाइल्ड वैलफेयर हो, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की तरफ से 11 प्रतिशत हो, हमारे पूर्वांचल में 11.4 प्रतिशत कम हैं। हम लोग शिक्षा की तरफ देखते हैं तो शिक्षा में उत्तर प्रदेश के आंकड़े 56.27 परसेंट हैं। भारत में 64.80 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, लेकिन मेरा पूर्वांचल पिछड़कर 54.27 परसेंट है। महिलाओं में सिर्फ 39.13 प्रतिशत को शिक्षा मिल रही है। हम देखें तो पूरे हिन्दुस्तान में नंबर ऑफ स्कूल प्रति लाख पॉपुलेशन पर 2007-08 में हिन्दुस्तान का औसत 70 प्रतिशत है और हमारे यहाँ पूर्वांचल में जूनियर बेसिक स्कूल 68 प्रतिशत हैं। पश्चिम में देखें तो 80 परसेंट हैं और बुंदेलखंड में देखें तो 104 परसेंट हैं। जूनियर स्कूल भी हमारे यहां 87 परसेंट हैं

जबकि और जगहों पर ज्यादा हैं। मैं इन आंकड़ों के द्वारा यह कहना चाहती हूँ कि पूर्वांचल में जितनी शिक्षा हमें चाहिए, उतनी नहीं है। खास तौर से मैं मैडिकल शिक्षा के संबंध में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। हमारे गोरखपुर में एक मैडिकल कालेज है जिसकी हालत बहुत ही खराब है। हम आपके माध्यम से मंत्री जी से यही रिक्वैस्ट करेंगे कि हमारे यहाँ दो-तीन मैडिकल कालेज पूर्वांचल में और बनाए जाएँ जिससे हम अपने लोगों को मैडिकल शिक्षा की सुविधा दे सकें। जो हमारे मैडिकल कालेज हैं, उनका नवीनीकरण किया जाए। खासकर वहाँ गोरखपुर का जो मैडिकल कालेज है, उसमें बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। हमारे पूर्वांचल में एक बहुत बड़ी बीमारी है जैपनीज़ एनसिफैलाइटिस। यह एक एपिडैमिक के रूप में चल रही है। इसका भी कोई ठीक इलाज नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ अभी भी बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं। हमारे युवा नेता राहुल जी ने सरकार से कहा था कि वह जो कर सकते हैं, ज़रूर करेंगे, पर स्टेट गवर्नमैंट ने जो उनकी राय थी, पूरी तरह नहीं मानी। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please do not disturb her.

राजकुमारी रत्ना सिंह : मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि एनसिफैलाइटिस को वारफुटिंग पर लिया जाए और इस बीमारी के इरैडिकेशन के लिए हमें कुछ करना चाहिए।

अब मैं खेती-बाड़ी पर आती हूँ। ये 2005-06 के आंकड़े हैं। पूरे हिन्दुस्तान में 42.40 परसेंट भूभाग पर खेती होती है। हम जब यूपी के आँकड़े देखें तो 78.6 परसेंट एरिया सोन है। मेरे पूर्वांचल में 74 परसेंट ही है जबकि पश्चिम यूपी में 90.2 परसेंट, सैन्ट्रल यूपी में 82 परसेंट और 60 परसेंट बुंदेलखंड में है। उत्तर प्रदेश के पूरे आंकड़े में भी हम लोग 4.6 परसेंट कम हैं। हम लोगों के यहां जो फर्टिलाइज़र आता है, उत्तर प्रदेश में ग्रास क्राप एरिया प्रति केजी 2006-07 में, उसमें पश्चिम यूपी को 174.09 दिया जाता है और मेरे पूर्वांचल को 151.79 दिया जाता है। इसमें भी कमी की जाती है। ...(व्यवधान) फर्टिलाइज़र तो दिल्ली से लखनऊ भेजना केन्द्र की जिम्मेदारी है लेकिन लखनऊ से हर जिले में खाद पहुँचाना तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb the hon. Member.

राजकुमारी रत्ना सिंह : हमारे उत्तर प्रदेश के जो आँकड़े मिल रहे हैं, फर्टिलाइज़र तो बहुत भेजा जाता है, हर साल सात परसेंट की बढ़ोतरी करके भेजा जाता है पर गरीब किसानों को फर्टिलाइज़र अभी भी नहीं मिल रहा है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb the hon. Member. You can speak when your turn comes.

राजकुमारी रत्ना सिंह : पूर्वांचल के किसानों को सबसे बड़ी परेशानी तो फर्टिलाइज़र की है। हमने उत्तराखंड में पूसा इंस्टीट्यूट भी दे दिए। हमने पंत नगर वाला इंस्टीट्यूट दे दिया, लेकिन अभी भी हमें वहां अच्छे बीजों की बहुत कमी पड़ रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि एक अच्छा एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट भी पूर्वांचल में दिया जाए, जिससे हमारे पूर्वांचल के किसानों को अच्छे बीज मिल सकें। हम आपने आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा, on gross value of agriculture output, per hectare of gross crop area at the current prices for 2005-06, पूरे हिन्दुस्तान के आंकड़े 26910 रुपए हैं। पश्चिमी यू.पी. में 39989 रुपए और पूर्वांचल में 24485 रुपए मिलते हैं। हम लोग करीब 13-14 परसैंट पश्चिम से पीछे हैं, per hectare gross crop area at current prices. पूर्वांचल में सबसे बड़ी परेशानी गन्ना किसानों की है। आप पूरे हिन्दुस्तान के आंकड़े देखिए, productivity of major crop per quintal hectare put together. पूरे हिन्दुस्तान में शुगर केन सन् 2006-07 के अंदर 690.22 था और हमारे पश्चिम में 608.71 है, पूर्वांचल में 523.61 है। हमारे यहां शुगर केन में भी बड़ी परेशानी है। पांच-सात सालों में, बल्कि बीस सालों में एक फ्लक्चुएटिंग शुगर पॉलिसी के कारण, जब-जब नयी सरकारें आती हैं तो शुगर पॉलिसी भी डिस्टर्ब हो जाती है। शुगर पॉलिसी की प्रोबलम के कारण पूर्वांचल में कई चीनी मिलें बंद हो गई हैं और हमारे गन्ना किसान कुछ चीनी मिलों को बेचने का प्रस्ताव भी कुछ साल पहले कर दिया। हमारे कई किसान नेपाल में जाकर अपना गन्ना बेच रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि शुगर केन पॉलिसी थोड़ी लोंग टर्म होनी चाहिए ताकि गन्ना किसान, मिल मालिक और सब मिल कर कुछ कर सकें। सबसे ज्यादा परेशान किसान होता है, जो अपना गन्ना मिल मालिक को बेच देता है और मिल मालिक उसे सही दाम नहीं देते। पूर्वांचल में गन्ना किसानों के लिए अभी हमें बहुत कुछ करना है। अगला ज्वलंत मुद्दा हमारे किसानों का है - जैसे फर्टिलाइजर, चीनी की भी प्रोबलम है। हमें बीज नहीं मिलता है, सबसे बड़ी प्रोबलम यह है कि हमारे यहां काफी नदियां नेपाल से पूर्वांचल में आती हैं - घघरा, सरजू, गंडक, राप्ती, तोंस है, जो नेपाल से शुरू होकर हमारे पूर्वांचल में आती हैं। जैसे ही धान लगाने का समय होता है, वे इतनी बाढ कर देती हैं कि हर वर्ष गोरखपुर एरिया में बाढ़ आ जाती है और किसान परेशान हो जाते हैं। बाढ़ रोकने के लिए कुछ चैक डेम्स बनाए जाएं, इसके कई फायदे होंगे। इससे हम लोग इलैक्ट्रीसिटी भी प्रडयूस कर सकते हैं, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में सबसे कम बिजली का उत्पादन है।

सभापति महोदय, पूर्वान्चल में सबसे कम बिजली का उत्पादन होता है और सबसे कम खर्च होता है क्योंकि बिजली हमें मिलती ही नहीं है, तो हम क्या खर्च करेंगे और कहां से खर्च करेंगे। वहां मुश्किल से छः-सात घंटे बिजली मिलती है। जितने घंटे बिजली मिलती है, उतने ही घंटे में हम जितनी बिजली खर्च कर सकते हैं, उतनी करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि नेपाल जब इन नदियों में पानी छोड़े, तो हमें सूचित करे और यहां चैक डैम्स बनाएं। उनसे इलैक्ट्रिसिटी की भी प्रोडक्शन हो सकती है और पूर्वान्चल को बिजली भी मिल जाएगी।

सभापति महोदय, बैंकिंग एवं फायनेंस में हमारे यहां क्रेडिट एंड डिपॉजिट का रेश्यो देखें, तो पूरे हिन्दुस्तान में वर्ष 2007-08 में 74.16 परसेंट, पश्चिम यू.पी. में 52.61 परसेंट है और पूर्वान्चल में 29.07 परसेंट है। इसलिए क्रैडिट डिपोजिट रेश्यो में भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। नंबर ऑफ शेडयूल्ड कॉमर्शयल बैंक्स, पर लाख ऑफ पापुलेशन इन दि ईयर 2007-08 में देखें, तो पूरे हिन्दुस्तान के आंकड़े 6.5 परसेंट हैं, लेकिन हमारे पश्चिमी यू.पी. में 5.00 परसेंट है और पूर्वान्चल में 4.2 परसेंट है। बैंकिंग सैक्टर में भी पूर्वान्चल में बहुत कमी है। फिर मैं एम्पलॉयमेंट एंड मैनपॉवर पर आती हूं। हमारे यहां परसेंटेज ऑफ मेल वर्कर्स टू टोटल पापुलेशन, पूरे हिन्दुस्तान में 30.40 प्रतिशत है। पश्चिम यू.पी. में 24.19 और पूर्वान्चल 22.02 प्रतिशत है। मेल वर्कर्स इंगेज्ड इन रूरल ग्रॉस वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एट करेंट प्राइसेस फॉर 2005 और 2006 को देखें, तो हिन्दुस्तान का 5536 है। हमारे वैस्टर्न यू.पी. का इंडिया के एवरेज से ज्यादा 8893 है। इसकी तुलना में हमारा पूर्वान्चल बहुत पीछे यानी 3731 है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारा पूर्वान्चल कितना पिछड़ा है। यदि आप पर कैपीटम इन्कम एट करेंट प्राइसेस फॉर 2005 एंड 06 देखें, तो पूरे हिन्दुस्तान का 25,956 है। वैस्टर्न यू.पी. का 17,083 है और हमारे पूर्वान्चल का सिर्फ 9,499 है। भारत के आंकड़े से 15 हजार रुपए

कम हैं और पश्चिम यू.पी. से पूर्वान्चल के 8 हजार रुपए कम हैं। इस तुलना से आप स्वयं देख सकते हैं कि हमारा पूर्वान्चल कितना पिछड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से यही आग्रह करूंगी कि इन विषयों पर खास ध्यान दिया जाए।

सभापति महोदय, हमारे पूर्वान्चल में हिन्दू, बुद्धिस्ट और मुस्लिम समाजों के बहुत ज्यादा धर्म स्थान हैं। हमारे पूर्वान्चल में पूरा बुद्धिस्ट रूट है। बाबा विश्वनाथ काशी में हैं। सारनाथ भी बनारस में हैं, लेकिन हमारे यहां कोई अच्छा इंटरनैशनल एयरपोर्ट नहीं है। वाराणसी में जो इंटरनैशनल एयरपोर्ट है, उस पर ज्यादातर चार्टर्ड फ्लाइट्स आती हैं। उस पर कोई इंडियन फ्लाइट्स नहीं आती हैं। वह एयरपोर्ट सिर्फ दिन के समय चलता है। कहीं से भी जाएं, तो बनारस का एयरपोर्ट आमूमन प्रातः 8.00 बजे से सायंकाल 4.00 बजे तक चलता है। उसके बाद कोई भी फ्लाइट बनारस के एयरपोर्ट से नहीं चलती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि बनारस एयरपोर्ट को एक अत्याधुनिक, मॉडर्न इंटरनैशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, जिससे थाईलैंड, श्रीलंका और चायना आदि से जो टूरिस्ट्स आते हैं, वे वहां सुगमता से पहुंच सकें। हिन्दू धर्म के श्रद्धालु भी बहुत दूर-दूर से बनारस आते हैं। बुद्धिस्ट रूट में आते हैं तो उनको भी इस इण्टरनेशनल एयरपोर्ट का लाभ मिल सके। हमारे इस क्षेत्र में टूरिज्म बढ़ेगा तो एक अच्छा एम्पलॉयमेंट का, एक अच्छा रोजगार का नया सोर्स मिलेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि वाराणसी एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जाये। हमारे यहां गोरखपुर में भी एयरपोर्ट है, जहां हर एक या दूसरे दिन हवाई जहाज जाता है, उसको भी अपग्रेड करने की जरूरत है।

वाराणसी कई धर्म के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है और यहां गंगा-जमुनी तहजीब है। वहां एक तरफ आप घंटों की आवाज सुनते हैं तो अजान भी सुनाई पड़ती है और इसके बीच में हम अपने लूम्स की आवाज भी सुनते हैं। मैं तो कहूंगी कि विश्व के सबसे अच्छे वीवर्स मेरे पूर्वांचल में रहते हैं, चाहे वाराणसी हो, भदोही हो, देवरिया हो या मिर्जापुर हो, सभी वीवर्स यहां रहते हैं। उनके हाथों में जो हुनर है, शायद विश्व में कहीं नहीं है। अब इन वीवर्स के साथ अन्याय हो रहा है। वे न्याय मांग रहे हैं। बनारस का ब्रोकेड और बनारस का रेशम पूरे विश्व में मशहूर है। पहले तो वहां हैंड वीविंग होती थी, फिर उन्होंने पावर लूम लगाये तो बिजली आनी बन्द हो गई तो फिर बेचारे वीवर्स उसी हालत में आ गये। आज उनको अच्छा यार्न नहीं मिलता है, क्योंकि यार्न हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से कहूंगी कि आप मंत्री जी से आप आग्रह करें कि यार्न के लिए सब्सिडी दी जाये, जिससे वे और यार्न इम्पोर्ट करें और बनारस और आसपास के जिलों में वीवर्स को फिर से एक नया जीवन मिले। एक्सपोर्ट के लिए भी उनको इंसेंटिव्स दिये जायें, जिससे चाहे कालीन हो, रेशम हो या ब्रोकेड हो, उसको वे बेच सकें।

मुझे विश्वास है कि वीवर्स के लिए यह सरकार बहुत कुछ करेगी। मैं 1-2 बिन्दु और जरूर कहना चाहूंगी कि हमारी कांग्रेस सरकार ने बैकवर्ड एरिया ग्राण्ट फंड शुरू किया, जो पूर्वांचल के कई जिलों में चल रहा है। बी.आर.जी.एफ. के नाम से यह है, पर बी.आर.जी.एफ. में हम लोगों को कई परेशानियां हो रही हैं। यह पैसा तो केन्द्र सरकार का है और केन्द्र सरकार जिले को पैसा भेजती है, पर हमारे जो एम.एल.एज़. हैं और वहां जो प्रशासन है, वे एम.पी. की राय नहीं लेते और वह पैसा जिस तरह खर्च होना चाहिए, वह नहीं हो पाता। मैं सभी एम.पीज़. की तरफ से कहना चाहूंगी, जो पूर्वांचल के एम.पीज़. हैं कि बी.आर.जी.एफ. में बिना एम.पी. की राय के कुछ कार्य नहीं हो, जिससे कि हम लोग अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर सकें। हम लोग जो प्रपोजल देते हैं, उसके अनुसार कुछ कार्य नहीं हो पाता है।

हमारी सरकार ने कुछ साल पहले नरेगा स्कीम शुरू की। आज पूरे हिन्दुस्तान में नरेगा स्कीम चल रही है। नरेगा में पूर्वांचल में बहुत कुछ काम करवाया गया है, पर अभी भी नरेगा में बहुत कुछ हम लोगों को परेशानी होती है। वहां के जो अधिकारी हैं, वे ऐसे काम करवा देते हैं, जो मानक के अनुरूप नहीं होते।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि नरेगा पर भी पूर्वांचल में खास ध्यान दिया जाए। ...(व्यवधान) उस पर खास ध्यान दिया जाए। उसमें कई परेशानियां हो रही हैं। ...(व्यवधान)

महोदय, मेरा प्रतापगढ़ एक बहुत ही पिछड़ा जिला है। पूर्वांचल का वह ऐसा जिला है, जहां एक भी इंडस्ट्री आज की डेट में नहीं है। एक इंडस्ट्री मेरे पिता जी ने लगायी, वह केंद्रीय मंत्री थे, वहां प्रताप आटो ट्रैक्टर्स फैक्ट्री लगी। लेकिन वर्ष 1989 के करीब उस समय राज्य सरकार ने एक प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ उसको बेच डाला। उसके बाद उसने सारे मूवेबल प्रापर्टीज उस फैक्ट्री से निकाल लीं। अंततः वह सिक मिल हो गयी। आज वह प्रताप आटो ट्रैक्टर्स बीआईएफआर में है। मैं चाहती हूं कि प्रताप आटो ट्रैक्टर्स को भारत सरकार ले ले। वहां एक मेडिकल कालेज खोले, क्योंकि वहां सौ से एक सौ पच्चीस एकड़ जमीन है। 231 जो नया नेशनल हाइवे डिक्लेयर हुआ है, उस पर प्रताप आटो ट्रैक्टर्स स्थित है। इसमें एक मेडिकल कालेज खोले, क्योंकि इसमें इफ्रास्ट्रक्चर अभी भी काफी मौजूद है और इसकी लोकेशन भी अच्छी है। मेडिकल कालेज खुल जाए, तो बहुत से लोगों को राहत मिलेगी या कोई फर्टिलाइजर प्लांट सरकार वहां लगा दे, जिससे कि मेरा प्रतापगढ़ जिला, जिसमें एक भी इंडस्ट्री नहीं है, इससे कुछ तो इंडस्ट्री वहां हो जाएगी। पूर्वांचल में सारी इंडस्ट्रीज राज्य सरकार की फ्लुक्चुएटिंग पालिसीज के कारण बंद होती जा रही हैं। शुगर बंद हो गयी, सीमेंट बंद हो गयी, जो ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : If you disturb, I will not allow you to speak. I will cancel your name. So, please do not disturb her.

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदय, एलिगेशन लग रहा है, तो क्यों नहीं बोलेंगे?

MR. CHAIRMAN: You will have your turn. At that time, you can speak. But if you get up once more, I will cancel your name.

राजकुमारी रत्ना सिंह : मैंने इसके आंकड़े रखे हैं कि मेरा पूर्वांचल जिसकी मैं एक निवासी हूं, वह कितना पिछड़ा है। वहां सात प्रतिशत पापुलेशन है और वह हर चीज में पिछड़ा है। वहां बैंकों की कमी है, इंडस्ट्री की कमी है और भी बहुत सी चीजों की कमी है। मैं चाहती हूं कि हमारे पूर्वांचल को एक ऐसा सोशियो इकॉनामिक पैकेज दिया जाए, जिससे यहां की जनता आगे बढ़ सके। यहां की जनता उठ सके और लाभ प्राप्त कर सके। हमारे पूर्वांचल के लोग मेहनती हैं और उनको मौका मिलेगा तो वे जरूर इतने ऊंचे उठ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल सबसे आगे की सिचुएशन में पहुंच सकता है। इसमें केंद्र सरकार की मदद की जरूरत है, क्योंकि राज्य सरकार इतना काम नहीं कर पाएगी, जितनी हमारी केंद्र सरकार कर पाएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे यही कहूंगी कि हमें एक स्पेशल पैकेज दिया जाए। हमारे वीवर्स को पैकेज दिया जाए, शुगर किसानों को, सभी किसानों को और पूर्वांचल के सभी निवासियों को एक एक्स्ट्रा हेल्प मिले जिससे कि हम लोग भी उठ सकें और सिर ऊपर उठाकर चल सकें।

श्री हुकमदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्या को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूर्वांचल के प्रश्न को उठाया। जिस विस्तार के साथ, मार्मिक पीड़ा के साथ, वेदना के साथ पूर्वांचल की व्यवस्था को वह यहां रख रही थीं, वह समझने लायक है और सुनने लायक भी है। मैं प्रार्थना करूंगा कि गैर-सरकारी संकल्प जब सदन में प्रस्तुत हों तो उसको किसी राजनीतिक दल से न जोड़ा जाए, क्योंकि जब हम राजनीति करने लगेंगे, तो सत्य और तथ्य को नहीं

पकड़ पाएंगे। मैं भी विपक्षी दल में रहा हूं। समाजवादी आन्दोलन से चला था चौधरी चरण सिंह जी के साथ, भाजपा तक की यात्रा, 1959 में ग्राम पंचायत का प्रधान बना था। मैं अपनी राजनीतिक यात्रा के पचास साल पूरे कर चुका हूं। ऐसी कौन सी पार्टी है जिसे हिन्दुस्तान में राज करने का अवसर नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ज्यादा जिम्मेदार है और अगर देश में कुछ अभाव रहा, हम नहीं कर पाए, तो हम भी उसके लिए बरी नहीं हो सकते, हम भी थोड़े-बहुत जिम्मेदार जरूर हैं। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से नहीं समझेंगे, तब तक राष्ट्र की एकता और अखंडता को ध्यान में रखकर समग्र विकास नहीं कर सकते। राष्ट्र का जितना विकास होना चाहिए, उतना नहीं हुआ, यह सत्य है। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्र का विकास ही नहीं हुआ।

हम 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुए थे। उस समय जहां खड़े थे और आज जहां खड़े हैं, अगर सोचा जाए, तो इन दोनों में गुणात्मक परिवर्तन है। लेकिन दिशा ठीक नहीं थी, दृष्टि सही नहीं थी और गति सही नहीं थी, इसलिए उस पर हम चिंतन करें। जहां पूर्वांचल की सीमा समाप्त होती है, वहां से मिथलांचल की सीमा प्रारंभ होती है। गोरखपुर-पडरौना की सीमा जहां समाप्त होती है, वहां नारायणी के उस पार बगहा से मिथलांचल की सीमा शुरू होती है जो किशनगंज, बंगलादेश के बार्डर तक जाती है। जस हालत पूर्वांचल की तस हालत मिथलांचल की। आपके यहां भी पूर्वांचल में नदियां नेपाल से निकलती हैं और नेपाल में जब वर्षा होती है तो अथाह पानी आकर हमारी सभी फसलों को ले जाता है, घर बर्बाद हो जाते हैं, जानवर बर्बाद हो जाते हैं, हम भी बर्बाद होते रहते हैं। उसी तरह मिथलांचल में है। जब नेपाल में वर्षा होती है, तो हमारे यहां भी पानी आ जाता है। हम बाढ़ से उजड़ते रहते हैं। बाढ़ का मिथलांचल या पूर्वांचल में कोई स्थायी निदान न निकला है, न निकलने की कोई संभावना है, क्योंकि नेपाल से नदियां आती हैं। एक बार ऊंचा पानी आकर नीचे फैलता है तो उसे हम किसी प्रकार रोक नहीं सकते। बिहार के लोग इस आंदोलन को मिथलांचल में चलाते थे कि कोसी, कमला, गंडक को रोकने के लिए नूनथर में, वराह क्षेत्र में, शीशा पानी में डैम बनाया जाए। वह नेपाल में बनेगा। किसी दिन राजनीतिक हालत बिगड़ जाए, नेपाल से हमारे संबंध बिगड़ जाएं, तो हो सकता है कि एक बार उस डैम का फाटक उठा दिया जाए तो तीन सौ फीट पानी आ जाएगा । पूर्वांचल और मिथलांचल के लोग समुद्र के गर्भ में डूब जाएंगे, उतने पानी में बह जाएंगे। यह राजनीतिक कारण से नहीं हो पा रहा है, इसलिए रुका हुआ है। लेकिन दूसरे उपाय किए जा सकते हैं। परिवहन हो, बिजली हो, अगर सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, तो विकास कहां से होगा। पूर्वांचल और मिथलांचल में टूटी-फूटी सड़कें हैं। हमने आजाद भारत में इतने दिन देखा।

एक बार मैं सड़क पर जा रहा था, तो आगे-आगे एक मोटर साइकिल वाला अपनी नई पत्नी को लेकर सिनेमा दिखाने ले जा रहा था। जब सड़क के गड्ढे में मोटर साइकिल हिचकोले मारती तो वह पलट-पलटकर हाथ लगाकर देखता था।

श्री दारा सिंह चौहान : क्योंकि उसकी नई-नई शादी हुई थी इसलिए वह पीछे हाथ लगा कर देख रहा था।...(<u>व्यवधान</u>)

श्री हुकमदेव नारायण यादव :मैंने उसे रोक कर पूछा कि पलट-पलटकर क्या देखते हो। वह कहने लगा कि मैं यही देखता हूं कि पीछे मेरी पत्नी बैठी है या किसी गड्ढे में गिर गई। ऐसी हालत में हम उस जगह रहे हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना होगी कि सड़कें ठीक हों। गांव-गांव को जोड़ा जाए। आप अनुकरण करिये। हरियाणा में जाइए, पंजाब में जाइए, सभी गांवों तक पक्की सड़कें बनी हुई हैं। जिस गांव में पक्की सड़कें बनी हुई हैं, वहां यातायात दुरुस्त है, परिवहन सेवा है, वह इलाका उन्नत है। जहां सड़कें नहीं है, परिवहन नहीं है, यातायात की सेवा नहीं है, वह इलाका सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। पिछड़े होने का कारण क्या है? पिछड़े होने का कारण है। जहां सरकार जिम्मेदार है, व्यवस्था जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, वहां हम खुद भी जिम्मेदार हैं। मैं पूर्वांचल और मिथलांचल का हूं। मैं जानता हूं कि हमने राजनीति का सबसे ज्यादा जातीयकरण किया, जाति का अपराधीकरण किया, अपराध का सामाजीकरण किया। हम इस बात के भुक्तभोगी हैं। मेरी आत्मा आज रोती है कि हम कितने गिर गए थे। हमारा नेता चाहे कितना ही भ्रष्टाचारी हो, अपराधी हो, चाहे जेल चला जाए, जेल से निकले, हाथी पर बिठाकर घंटी बाजा बजाकर उसका स्वागत किया जाए, लेकिन जब वह सामाजिक समारोह में जाता है, तो अपनी जाति में पूजित होता है। वह भ्रष्टाचारी नेता सामाजिक समारोह, सांस्कृतिक समारोह में कहीं भी जाता है तो उसे ऊंचे आसन पर बिठाया जाता है।

<u>17.00 hrs.</u>

उसकी आरती उतारी जाती है, माला पहनायी जाती है, जय-जयकार किया जाता है और कहा जाता है कि मेरा नेता कैसा हो, इन्हीं के जैसा हो, जो सब कुछ खायेगा, देश को मिटायेगा, अपना नाम उठायेगा। हम उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। इसलिए पूर्वांचल, मिथलांचल और राज्य के सभी पिछड़ों इलाकों का तब कल्याण होगा जब उस देश के नयी पीढ़ी के नौजवान, उस इलाके के लड़के-लड़कियां, ये नयी पीढ़ी वाले एक दिन उठें, साहस करें और अपनी जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों की अर्थी निकालें और अग्नि की चिता में जाकर भस्म कर दें। जिस दिन जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को जलाकर राख कर देंगे, उस दिन उस राख से ऐसी क्रान्ति निकलेगी जिससे पिछड़े इलाके का संभव और समग्र विकास हो सकेगा। यह हमारा प्रधान रोग है और इस रोग का निदान चाहिए।

माननीय सदस्या ठीक कह रही थीं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सभी गन्ना मिलें बंद हैं। मिथलांचल में सभी गन्ना मिलें बंद हैं। मेरे क्षेत्र में दस किलोमीटर की दूरी पर तीन चीनी मिलें -- रैयाम, लोहट और सकड़ी बंद पड़ी हुई हैं। वहां गन्ना ही एकमात्र सबसे बड़ा उद्योग था, जिससे चीनी बनती थी, किसानों को नकदी फसल थी और उनके घर में खुशहाली आती थी। लेकिन देश के कुछ इलाकों के शुगर लॉबी वालोंने सोचा कि उत्तर प्रदेश और बिहार, जो सबसे ज्यादा चीनी पैदा करने वाला है, जब तक वहां की चीनी मिलें बंद नहीं होंगी तब तक उनके इलाकों के चीनी मिल वालों का कल्याण नहीं होगा। इसलिए उन्होंने षडयंत्र के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलों को बंद कर दिया। महोदय, हमारे गन्ने की किस्म अच्छी है, हमारी रिक्वरी अच्छी है, हमारे किसान मेहनती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जहां भी कमाने के लिए जाते हैं, वहां मेहनत करते हैं। आप चाहे कोलकाता, मुम्बई, दिल्ली या जहां कहीं भी शहर में चले जाइये, वहां आपको वे मेहनत करते हुए मिलेंगे। वे पसीना बहाते हैं, महलों और अट्टालिकाओं को सजाते हैं और उनकी छाया में सोकर अपनी रात गुजारते हैं। आज दिल्ली में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मिथलांचल के कम से कम पांच लाख लोग फुटपाथ पर सोते हैं। वे पेड़ के नीचे सोते हैं, पेड़ के नीचे जीवन जीते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में शादी करते हैं और वहीं बच्चे पैदा करते हैं और वहीं बूढ़े होते हैं। वे फुटपाथ पर ही मर जाते हैं फिर उनकी लाश लावारिस जैसे रह जाती है। यह क्यों होता है? यह इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहां आर्थिक विकास नहीं है। हमारे यहां सड़क, बिजली नहीं है। माननीय सदस्या कह रही थीं कि बिजली तो कब आती है, कब जाती है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। बेटी जब ससुराल जाती है, तो ठिकाना रहता है कि त्यौहार पर आयेगी। लेकिन जब बिजली जाती है, तो कोई ठिकाना नहीं। वह आयेगी या ससुराल में ही रह जायेगी या मायके में ही रह जायेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं।

भारत सरकार के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चलायी जाती है। श्रीमान् जी माफ कीजिए कि बिजली लगायी जा रही है, लेकिन यह कहते हैं कि खम्भा, तार, ट्रंसफार्मर आदि हम देंगे और उसे लगवा भी देंगे, लेकिन बिजली राज्य सरकार पैदा करे। अगर कोई आदमी कहे कि चूल्हा हम खोद देंगे, बर्तन हम देंगे, बनाने वाला हम देंगे, लेकिन चावल-दाल का इंतजाम तुम करो, तो हम उन्हें कहेंगे कि हम जलावन का इंतजाम खुद कर लेंगे, बर्तन का इंतजाम खुद कर लेंगे, तुम मुझे चावल-दाल दे दो। भारत सरकार कहती है कि बिजली खुद पैदा करो। अब हम बिजली कैसे पैदा करेंगे? हमारे पूर्वांचल और मिथलांचल में न कोयला

है, न गैस है और न यूरेनियम है। इन्हीं तीन चीजों से बिजली बनती है। हम कोयला कहां से लायेंगे? जहां कोयला है, अब वह चाहे झारखंड में हो या जिस एरिया में हो, पूर्वांचल और बिहार को आप कोयले के दस खानों का पट्टा दे दीजिए। हम अपनी खान से कोयला निकालेंगे, अपने रेट पर लायेंगे और अपने बिजली घर बनायेंगे, नहीं तो आप हमें गैस दीजिए। अब गैस आप पैदा करते हैं। आप हमें गैस दीजिए जिससे हम बिजली घर बनायें। बिहार में दो बिजली घर बने हुए हैं। उनका शिलान्यास हो गया है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में उनका शिलान्यास किया गया, लेकिन वे आज तक नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अब हम पैसा कहां से लायें? आप टैक्स लेंगे, आयकर लेंगे, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कपड़े, सलाई, दवाई, नमक, हल्दी-मिर्च, सड़क आदि पर आप टैक्स लेंगे। यानी सब टैक्स आप लेंगे और हमें कहेंगे कि पैसा तुम लाओ। मेहनत करें हम, मौज उड़ाओ तुम। ऊपर से कहो कि खाने-ठिकाना का इंतजाम खुद करो। हमें परिश्रम और पसीने का भी हिस्सा नहीं मिलता है, इसलिए मैं केन्द्र सरकार को आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। एक नीति बने कि जो पिछड़े इलाके हैं, चाहे वह बुंदेलखंड हो, चाहे मिथिलांचल हो, पूर्वांचल हो, चाहे राजस्थान का इलाका हो, उसका विकास होना चाहिए। आज कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां पिछड़ापन नहीं है। क्या महाराष्ट्र के सभी इलाके बराबर हैं, क्या गुजरात में सभी इलाके बराबर हैं, क्या राजस्थान में सभी इलाके गंगानगर जैसे हैं, क्या बिहार के सभी इलाके नालन्दा और हाजीपुर जैसे हैं, क्या छत्तीसगढ़ में सभी इलाके बराबर हैं? हर राज्य में पिछड़ा इलाका है, उनको जानबूझकर पीछे रखा गया है। जो इलाका जितना पीछे है, वह सामाजिक दृष्टिकोण से भी उतना ही पीछे है, जो सामाजिक दृष्टि से पीछे हैं, उनको प्रशासन में हिस्सा नहीं मिला, राजनीति में हिस्सा नहीं, मंत्रिमंडल में हिस्सा नहीं, मुख्यमंत्री में हिस्सा नहीं, अफसरों में हिस्सा नहीं, न दिल्ली सरकार में हिस्सा, उनको कहीं हिस्सा मिला नहीं। उत्तर प्रदेश में माननीय चौधरी चरण सिंह थोड़े दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने किसान जातियों को सबसे पहले मंत्रिमंडल में स्थान दिया था, इसलिए उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह बिहार तक के किसानों के नेता रहे। उनसे पहले कौन पूछता था पिछड़े जाति के लोगों को। हमारा भी दुर्भाग्य है कि जो पिछड़े इलाके का नेता है, वह अपने नेता के पीछे दुम पकड़कर चलते रहता है, वह अपनी आवाज नहीं उठाता है। हम तो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर, राजनीतिक दृष्टि से कमजोर, प्रशासनिक दृष्टि से कमजोर, सामाजिक दृष्टि से कमजोर हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। बच्चे को कैसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, बच्चा न बढ़िया पढ़ेगा, न कंप्टीशन में जाएगा, न ऊंची कुर्सी पाएगा, न हाकिम बनेगा, न आईएएस-आईपीएस बनेगा, न इधर से पैसा आवे, न उधर से पैसा आवे, न गन्ना मिल चले, गन्ने की खेती भी मरती जा रही है। यह एक सुनियोजित षडयंत्र है कि पिछड़े इलाके को पिछड़ा बनाकर रखो, उनको दबाकर रखो। वे दबे रहें, उनकी आवाज नहीं उठने पाए क्योंकि अगर वे ताकतवर हो जाएंगे, तो उनकी आवाज गूंजने लगेगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है , पिछड़ापन दूर होगा तब सामाजिक उन्नति होगी जब, पिछड़ापन दूर होगा तब, शैक्षिक दृष्टि से उठेंगे जब, पिछड़ापन दूर होगा तब, आर्थिक दृष्टिकोण से उठेंगे जब, पिछड़ापन दूर होगा तब, प्रशासनिक दृष्टि से उठेंगे , इसीलिए जातियों के आधार पर जो आरक्षण है, वह अपनी जगह पर रहे, उसका मैं समर्थक रहा हूं, उसके लिए संघर्ष करता रहा हूं। लेकिन उसके साथ-साथ एक नए सिद्धान्त को लागू किया जाए कि जो इलाके आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, वहां के लोगों को प्रशासनिक सेवाओं में उसी हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाए, उनके लिए अलग से आरक्षण किया जाए तब कहीं उनका मुकाबला हो सकता है। आज कौन सा बैंक गरीब की बात सुनता है? जो इलाका गरीब है, वहां हाकिम उनकी क्या बात सुनेगा। पूर्वांचल की जो पीड़ा है, वही पीड़ा मिथिलांचल की है और हम उसी पीड़ा से ग्रस्त हैं। बुंदेलखंड के लिए आपने क्या किया है? क्या बनाते हैं आप? हमें गरीब बनाते हैं, दिल्ली की सरकार से कोई जाए और कहे, हम तुमको सोना देंगे, चांदी देंगे, कंबल देंगे, कपड़े देंगे। मुझे भिखमंगा बनाकर रखो, गरीब बनाकर रखो, भूखा रखो और मुझे खाने में हलवा-पूड़ी का लोभ दिखाकर अपनी जय-जयकार कराओ। यह सबसे बड़ी राजनीतिक अधमता है, यह सबसे बड़ा प्रशासनिक पाप है क्योंकि गरीब की गरीबी का उपहास करना ठीक नहीं है। हम गरीब हैं, हमको कहोगे, हम तुम्हारे लिए स्पेशल पैकेज दे रहे हैं? क्या दे रहे हो आप? क्या अपनी जायदाद बेचकर दे रहे हो, कोई अपना कपड़ा बेचकर दे रहे हो, क्या अपनी घरवाली के जेवर बंधक रखकर दे रहे हो, कहां से स्पेशल पैकेज दे रहे हो? आप भारत सरकार के खजाने से स्पेशल पैकेज दे रहे हो। वह खजाना मेरा भी है। वह खजाना इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर, निर्धन, निर्बल, मेहनतकश लोगों का है। इन्हीं लोगों के पसीने से भारत सरकार का खजाना भरा हुआ है। उस पसीना बहाने वाले को उसका लाभ मिलना चाहिए। अफसोस है जहां पसीना है, वहां पैसा नहीं है और जहां पैसा है, वहां पसीना नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पिछड़ापन तभी दूर होगा जब पैसा पसीने वाले के पास में जाएगा और जहां बिना पसीने के पैसा है वहां से पैसा लाओ और पसीने वाले के पास पहुंचाओ, तब पसीने वाला आगे बढ़ पाएगा और देश से पिछड़ापन मिट जाएगा, चाहे वह लालसिंह का कश्मीर हो, चाहे जम्मू हो, चाहे बिहार हो, चाहे और कोई दूसरा प्रदेश हो, यही बात हमें चाहिए।

अंत में मेरी प्रार्थना है कि हमारे झारखंड के साथी बैठे हुए हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र और जहां-जहां पहाड़ी इलाके हैं, उनमें बसने वाले जो भी लोग हैं वे एससी और एसटी हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी हालत इसलिए बिगड़ी हुई है कि उन पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, उनकी दशा पर कोई सोचना वाला नहीं है। " कमाए कोई, खाए कोई, पसीना बहाए कोई, मौज उड़ाए कोई।" पुराने जमाने में जमींदार थे, जमींदारी बेचकर लाते थे और दरवाजे पर मुज़रा करवाते थे, आज सरकार ऐसी आती है जो गरीब किसान, निर्धन, निर्बल, दलित, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति-जनजाति के पसीने से मौज उड़ाती है, ऊपर आते हो और हमसे पैकेज के नाम से जय-जयकार करवाते हो। ओ जय-जयकार कराने वाले, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि अपना जय-जयकार कराना बंद करो, अगर तुम ऐसी ही राजनीति करते रहोगे तो एक दिन हिंदुस्तान का भूखा, नंगा, दलित, अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़े, अति-पिछड़े, किसान-मजदूर उठकर आयेंगे और जिस दिन वे दिल्ली की तरफ मार्च कर देंगे, उस दिन रामधारी दिनकर के शब्दों में कहेंगे " हटो स्वर्ग के दूत मैं स्वर्ग लूटने आता हूं, छोड़ों सत्ता की जनता दिल्ली आती है।"

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजकुमारी रत्ना सिंह जी के संकल्प पर, पूर्वांचल के विकास पर विकास पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। चूंकि यह प्राइवेट मैम्बर बिल है और इसमें सभी मैम्बरों को पूरा अधिकार होता है कि वे अपनी बात रखें। जब राजकुमारी जी बोल रही थीं, तो माननीय दारासिंह जी यूपी के मामले पर बड़ा इंटरप्ट कर रहे थे। जबकि इस संकल्प में देखा गया है कि व्यक्ति अपनी व्यथा, अपनी अभिव्यक्ति सदन में व्यक्त करता है।

आंकड़े बताते हैं कि पूर्वांचल में 28 जिले आते हैं। इलाहाबाद, प्रतापगढ़, गाजीपुर, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, भदौही, सिद्धार्थ नगर, गौंडा, बलरामपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, बलिया, फैजाबाद, सुल्तानपुर, कौशाम्बी, देवरिया, फतेहपुर, वाराणासी, जौनपुर, सोनभद्र, बस्ती, संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, आजमगढ़, मऊ, बाराबंकी, चंदौली और अम्बेडकर नगर। कुल 28 जिले आते हैं। हमने पूर्वांचल के विषय से संबंधित सामग्री लाइब्रेरी से मंगवाई थी, जिसमें 13वें वित्त आयोग से पूर्वांचल के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 80 हजार करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मांगने की बात कही थी, जबकि वर्ष 2001 की जनगणना से देखें तो इस आंकड़े की स्थिति कुछ और ही है। सामरा समिति की सिफारिश को अगर देखा जाए, तो उस संदर्भ में समिति ने भी कहा कि पूर्वांचल के विकास के लिए विशेष पैकेज देने की जरूरत है। वर्ष 2001 की जनगणना से 36.82 का यहां जो आंकड़ा दिया है, मुझे याद है कि फतेहपुर से ले कर गोरखपुर तक, हमारे इलाहाबाद से सटा हुआ फतेहपुर, कौशांबी, गोरखपुर और उसके बाद मिथलांचल बिहार का एरिया आता है। रत्ना जी, जब आप बोल रही थीं, तब आपने इलाहाबाद का नाम नहीं लिया। हमारे देश की आजादी का केंद्र बिंदु इलाहाबाद रहा है। आनंद भवन, स्वराज भवन ऐतिहासिक नगरी है और छह-छह लोग देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। राहुल गांधी जी सदन में उपस्थित हैं और मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस बारे में आप विस्तार से बोलेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पूर्वांचल के

विकास की चर्चा चल रही है। मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में कौशांबी का जो सर्वे हुआ 73.12 और प्रताप गढ़ का 76.53। यह बात सत्य है कि वर्ष 1998 में जब मैं प्रथम बार जब चुन कर आया था, उस वक्त फतेहपुर के माननीय सदस्य ने एक क्वैश्चन सदन में लगाया था। उन्होंने प्रश्न किया था, उसमें उत्तर प्रदेश के दस या बारह जिले लिए गए थे, जिसमें हमारा फतेहपुर, कौशांबी और प्रतापगढ़ शामिल था। उसमें 45 करोड़ रुपए की हर डिस्ट्रिक्ट की योजना आई थी, जिससे बहुत अच्छा कार्य भी हुआ था। उस 45 करोड़ रुपए से विकास संबंधित जितने भी विभाग थे, उन्हें पैसा वितरित किया गया था और काफी विकास हुआ था। जहां तक पूर्वांचल को देखा जाए, तो इलाहाबाद ही केंद्र बिंदु बनता है। गंगा, यमुना, सरस्वती की तहजीब और पावन पवित्र धरती को मैं नमन करता हूं, जहां पंडित मोती लाल नेहरू से लेकर पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी का इलाहाबाद से संबंध रहा है। गांधी-नेहरू परिवार के बारे में देखा जाए, तो इलाहाबाद पालिटिकल केंद्र बिंदु रहा, आजादी का केंद्र बिंदु रहा और बहुत ऐतिहासिक वहां का महत्व रहा है चाहे धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उसे देखा जाए या सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, इलाहाबाद का बहुत महत्व है। भारद्वाज आश्रम, संगम है, जहां प्रति वर्ष कुम्भ मेला लगता है, अर्धकुम्भ मेला लगता है। यहां उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट भी है और केंद्रीय सरकार के बहुत से दफ्तर भी वहां है। यहां उत्तर प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा आयोग भी है। केंद्र और यूपी सरकार के कई दफ्तर यहां हैं। इस कारण भी इलाहाबाद का काफी महत्व है। जहां तक देखा जाए, जो परिप्रेक्ष्य हमने आपके सामने रखें हैं, इलाहाबाद का उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया है। इसी सदन में श्री जयपाल रेड्डी जी, जो हमारे शहरी विकास मंत्री जब उत्तर दे रहे थे, श्री सोमनाथ चटर्जी स्पीकर के रूप में पीठ पर बैठे थे, मैंने सवाल किया था कि पंडित जवाहर लाल नेहरू शहरी विकास योजना के नाम पर हम देश के बड़े-बड़े महानगरों को तो ले रहे हैं, लेकिन जिस शख्सियत के नाम से यह योजना है, उनसे संबंधित शहर इलाहाबाद को आप भूले जा रहे हैं। उस समय आदरणीय सोनिया गांधी सदन में बैठी थीं, हमने कहा कि मैडम वह आपका घर और ससुराल है, इसलिए इस शहर को जरूर शामिल कीजिए। यह सवाल मैंने पिछली लोकसभा के समय में उठाया था, लेकिन आज तक इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना के तहत कोई काम ही नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या बात है, वहां पैसा ही नहीं जा रहा है। आदरणीय राहुल जी से मैं निवेदन करूंगा कि इलाहाबाद में पंडित जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण के लिए पैसा क्यों नहीं जा रहा है, क्यों विकास नहीं हो रहा है, इस बारे में आप विशेष तौर से ध्यान दें। मैंने आपको एक पत्र भी दिया था, जब मैंने प्रश्न रखा था। अभी कुंभ मेले संगम नगरी की बात कही जा रही थी। यहां देश-विदेश से करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। धार्मिक ग्रंथों और पुराण में कहावत है कि जो संगम में डुबकी लगाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह स्वर्ग में जाता है। यह धारणा है। आज भी पूर्वांचल प्रदेश में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है। यहां बहुत पर्यटक आते हैं। यहां बौद्ध सर्किट भी है। कौशाम्बी, हमारा जिला है जहां से मैं सांसद हूं, सारनाथ, बनारस, श्रावस्ती और कई ऐसे जिले हैं जहां विदेशी पर्यटक आते हैं। इलाहाबाद में केवल एयरफोर्स बेस एयरपोर्ट है। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा होना चाहिए चाहे वाराणसी को बना दें या इलाहाबाद में इरादतगंज, यमुना के पार है, को बना दें। यहां पुराना एयरपोर्ट बना है इसे अंतरराष्ट्रीय अड्डे में बदल दें तो बहुत अच्छा होगा।

महोदय, यहां बीआरईजीएफ की बात कही गई है। सम्मानित सदस्या रत्ना जी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर बीआरईजीएस के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इसका पुराना नाम राष्ट्रीय सम विकास योजना था और वर्तमान में इसे हम बीआरईजीएस योजना के नाम से जानते हैं। केंद्र सरकार से डॉयरेक्ट पैसा पिछड़े जिलों को जाता है। लेकिन इसमें एमपी की कोई भागीदारी नहीं है। उन्हें पूछा ही नहीं जाता है, उनको पता ही नहीं लगता है, केवल अधिकारी इसका भोजन करते हैं। मैं चाहता हूं कि बीआरईजीएफ के पैसे में एमपी की भागीदारी होनी चाहिए। इसी तरह से पीएमजीएसवाई में हमसे कुछ नहीं पूछा जाता है, न उद्घाटन कराया जाता है और न हमें बुलाया जाता है। लेकिन इसमें व्यवस्था होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि स्थानीय सरकारों या राज्य सरकारों में कोई हस्तक्षेप हो लेकिन जो योजनाएं यहां से डायरेक्ट जाएं, उनमें मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट को जरूर सहभागी बनाया जाए और उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।

महोदय, हमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, सतर्कता निगरानी समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है। सत्र 19 नवंबर से शुरू हुआ था। मैं यह सत्र शुरू होने से पहले 12 नवंबर को अटैंड करके आया हूं। इसमें पिछली कार्यवाही को वीटो करते ही तीन-चार घंटे हो गए, भोजन आया, लोगों ने पैकेट में भोजन किया और चले गए। अगर हम किसी जांच के लिए लिखते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो हमारी कोई सहभागिता या भागीदारी नहीं होती है। अगर आपने मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट, लोक सभा या राज्य सभा को अध्यक्ष बनाया है तो आपको कम से कम इतना तो करना चाहिए कि आर्थिक प्रस्ताव पर सिन्नेचर हो, जांच कराई जाए, पनिशमेंट की व्यवस्था हो और इसके साथ वित्तीय पावर भी देनी चाहिए तभी हम, ग्रामीण विकास का जो सपना, महात्मा गांधी से लेकर स्व. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देखा था उस परिकल्पना को सफल कर पाएंगे।

महोदय, अभी सांसद निधि की बात कही गई। कल एक सम्मानित सदस्य ने सप्लीमेंटरी बजट की बात रखी थी। मेरे ख्याल से सांसद निधि स्व. नरसिम्हा राव जी के समय से शुरू हुई थी। तब से यह अब तक एक से दो करोड़ हुई है। आज स्थिति यह है कि यह राशि वर्ष 1998 से वही दो करोड़ है। आप देखिए कि दाम कितने बढ़ गए हैं। एक किलोमीटर सड़क एक साल में बना सकते हैं। एक विधायक को, हमारे प्रदेश में एक, सवा या डेढ़ करोड़ रुपए मिलते हैं। उसे पूर्वांचल निधि और भी निधियां जैसे बीआरईजीएस में राशि मिलती है। जनता हमें भी वोट देती है और जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि यह काम करवाइए। हम कहां से करवाएं? या तो इस सांसद निधि को खत्म कर दिया जाए या दस करोड़ कर दिया जाए क्योंकि हम अलग बदनाम होते हैं। यह मेरी मांग है।

महोदय, जहां तक पूर्वांचल के विकास की बात है। इसी सदन में योगी आदित्यनाथ ने बीमारियों और स्वास्थ्य के बारे में कॉलिंग अटैंशन और प्रश्न काल में कहा था। यह बात सत्य है कि पूर्वांचल के कुछ हिस्से गोरखपुर से लेकर तराई एरिया में आते हैं। जो हमारा लोक सभा क्षेत्र है, वह गंगा और यमुना के बीच का हिस्सा है। वहां तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। यदि बाढ़ आ गई तो बाढ़ खत्म होने के बाद वहां भयानक बीमारियां आती हैं। यह बात सबको मालूम है। अगर सूखा पड़ गया तो और भी बीमारियां आती हैं। इनसिफलाइटिस के बारे में अभी रत्ना जी ने बताया। चेचक की बीमारी के बारे में कहा जाता है कि इसका बिल्कुल उन्मूलन हो गया है। लेकिन आज भी गांवों मे लोगों को बड़ी और छोटी चेचक निकलती है। जॉन्डिस होता है, मलेरिया होता है, दिमागी बुखार होता है, डेंगू होता है, कालाजार होता है। इस तरह की तमाम बीमारियां पूर्वांचल में हैं। इनके लिए मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि एक केन्द्रीय दल वहां जाए और पूर्वांचल के तमाम सुदूर इलाकों और खासकर पिछड़े इलाकों में जाकर अध्ययन करके वहां वैक्सीन्स की व्यवस्था करे। तभी वहां इन बीमारियों का इलाज हो सकता है।

महोदय, आपने घंटी बजा दी है, जबकि प्राइवेट मैम्बर बिल पर बोलने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। इस पर हमें बोलने दीजिए, यह हम लोगों का ही समय होता है। ...(व्यवधान)

यदि शिक्षा के मामले में देखा जाए तो पूर्वांचल में ज्यादातर शेडयूल्ड कास्ट्स, शेडयूल्ड ट्राइब्स, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों की बहुलता है और इन्हीं के अंदर गरीबी, गुरबत है। श्री राहुल गांधी जी ने बड़ी अच्छी जगह चुनी है और वहां जाकर गरीबों के बीच में बैठकर आपने सब कुछ देखा भी है। इसके अलावा मल्टी-सैक्टोरल डैवलपमैन्ट प्लान के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय जहां रहते हैं, उनके डैवलपमैन्ट की बात इस सरकार ने कही है। श्री रंगनाथ मिश्र जी की रिपोर्ट के बारे में भी हम लोगों ने सदन में मामला उठाया था कि वर्ष 2007 में जब आयोग ने रिपोर्ट दे दी तो अब तक सरकार को इसे सदन के पटल पर रखना चाहिए था, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। आज आप अल्पसंख्यकों की बस्तियों में चले जाइये और उनकी स्थिति को देखिये तो आप देखेंगे कि एस.सी. और एस.टी. से भी ज्यादा बतदर

उनकी स्थिति है। मैं समझता हूं कि सरकार को उनकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है और इसके लिए सरकार को अलग से बजट की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

महोदय, अभी जब मैं रत्ना जी से बात कर रहा था तो वह कुछ जातियों का नाम ले रही थीं। मैं बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश में तथा जहां जंगली एरियाज हैं या बहुत से प्लेन एरियाज हैं, जहां आदिवासी रहते हैं, उन्हें घूमन्तु कहते हैं। आज भी करीब 227 ऐसी जातियां हैं, जिनके लोगों की संख्या करोड़ों में हैं। उनके सिर पर न कोई छत है, न उनके पास कोई रोजगार है, न उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है। बस वे लोग घूमते रहते हैं। उन लोगों की खानाबदोश की जिंदगी है। कभी जंगलों में जायेंगे, कहीं प्लेन में खुले आसमान के नीचे टैंट्स लगाकर रहते हैं और वहां थोड़ी बहुत जड़ी-बूटियां और दवा आदि बेचकर फिर आगे बढ़ जाते हैं। उनकी जिंदगी के बारे में भी हमें इस सदन में सोचना पड़ेगा। हमारे सम्मानित सदस्य, श्री राजा रामपाल जी यहां नहीं बैठे हैं, उन्होंने इस विषय को सदन में उठाया था। मैं कहना चाहता हूं कि ये 227 जातियां आज भी समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग-थलग हैं। उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। यह बात सही है कि उनकी जिंदगी कुत्ते-बिल्ली से भी अधिक बदतर है। यदि हम लोग एक कुत्ता या बिल्ली भी पालते हैं तो बड़े प्यार से उसे अपनी ए.सी. गाड़ी में घुमाने ले जाते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी के बारे में हम लोगों ने आज तक नहीं सोचा। इनमें आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जाति और पिछड़ी जातियों के लोग भी हैं। इसलिए उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। इन जातियों की संख्या पूर्वांचल में बहुत अधिक है। इसलिए मैंने इनका उल्लेख किया है। इनका जो पुश्तैनी रोजगार है, उससे हमें जोड़ना पड़ेगा, जो उनका पुश्तैनी रोजगार चला आया है, जैसे निषाद, मल्लाह है, जो गंगा, यमुना या अन्य नदियों के किनारे रहते हैं। उन्हें मछुआरे बोलते हैं। उन्हें हमें रोजी-रोटी से जोड़ना पड़ेगा। घाट का पट्टा, नाव का पट्टा, बालू का पट्टा, मछली पकड़ने का पट्टा ये सब उन्हें मिलना चाहिए। वे केवट लोग हैं। वहां केवट लोग हैं, भगवान राम सिंगरूपुर एक ऐतिहासिक जगह है जहां भगवान राम ने नाव से गंगा नदी पार की थी। उसके बाद हमारे क्षेत्र कौशाम्बी से होकर यमुना पार करके चित्रकूट गये। उन केवटों की स्थिति बहुत खराब है। आज उनकी हालत यह है कि वे कामरेड बनकर लाल सलाम नाम की सेना बनाकर आज हथियार लेकर यमुना के किनारे खड़े हुये हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रहती है। आज वे भी आतंकवादी बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इन लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा कि उनका जो पुश्तैनी रोज़गार है, उस रोजगार से उन्हें जोड़ना पड़ेगा। इसके किनारे बसने वाले हर जाति के लोग हैं जो बीड़ी बनाकर अपना जीवन-यापन करते हैं। जब तम्बाकू का प्रयोग करते हैं तो उन्हें टी.बी. हो जाती है। श्रम मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं, उन्होंने ऐसे लोगों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की है। कौशाम्बी जनपद में कम से कम इन लोगों के लिये स्पेशल सीजीएचएस का अस्पताल होना चाहिये क्योंकि वहां कोई अस्पताल नहीं है। इलाहाबाद में करोड़ों की संख्या में बीड़ी मजदूर रहते हैं। इसी प्रकार चारपाई बुनने के डोरी बनाते हैं। गगा नदी से मूंज लाते हैं, बान बनाकर उसे बेचते हैं। बर्तन बनाने वाले लोग शमसाबाद में रहते हैं। मिट्टी लाकर बर्तन बनाये जाते हैं। हमारे यहां तांबे का बर्तन, पीतल का बर्तन बनता है लेकिन वहां के लोगों की स्थिति यह है कि दूर से लोग आते हैं और वहां की मिट्टी उठाकर ले जाते हैं। उस मिट्टी में भी बहुत कुछ है।

सभापति जी, माननीय सदस्य चले गये हैं। भदोही में कालीन का काम होता है। पूर्वांचल के इस भाग से कालीन विदेशों में जाते हैं। बुनकर लोग हैं। प्रतापगढ़ में परियांवा है जहां के तमाम बुनकर यह कार्य करते हैं। राजकुमारी जी ने अपने क्षेत्र के बारे में यह नहीं बताया जिसे मैं बताकर पूरा कर रहा हूं.। वाराणसी में साड़ियां बनती हैं. कानपुर की चप्पल प्रसिद्ध हैं जो पूर्वांचल में आते हैं।. सरकार को इन लोगों के बारे में गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग या आदिवासी लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, उनके बच्चे जो कुपोषण के शिकार हैं, हमारी जो महिलायें हैं, उनके अंदर हिमोग्लोबिन की कमी है जिस से हमेशा ये महिलायें और बच्चे बीमार रहते हैं.। उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, उनकी शिक्षा के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा।

सभापति जी, अगर हमारे यहां रेल कनैक्टिविटी को देखा जाये तो मालूम होगा कि वहां परिवहन की भारी कमी है। सरकार कहती है कि मुगलसराय से लेकर कोलकाता तक मेन सड़क पूर्वांचल से होकर केवल कुछ जिलों में से होकर गुजरती है। अगर देखा जाये तो हम लोग बराबर उस क्षेत्र की स्थिति के बारे में सवाल उठाते रहते हैं। कभी नियम 377 के अधीन तो कभी शून्य प्रहर के तहत या प्रश्नकाल में मामला उठाते रहते हैं. लेकिन यह काम कभी पूरा नहीं हो पाया है। जैसे भरवारी-सिराथू-मनौरी में ऊपरिगामी पुल की बात है, इलाहाबाद में नवसृजित जिला कौशाम्बी बना हुआ है, वहां पर कुंडा में भी घंटों जाम लगा रहता है। अगर ऊपरिगामी पुल न बना तो नये जिले का कोई महत्व नहीं रहेगा और न पूर्वांचल के विकास की कोई बात कही जा सकती है। भरवारी में रेल गोदाम की व्यवस्था नहीं है क्योंकि खाद की कमी है, तमाम अनाज वहां इलाहाबाद से होकर नैनी से होकर कौशाम्बी जाता है, अगर गोदाम की व्यवस्था हो जाये तो अच्छा होगा। हर स्टेशन पर सुलभ शौचालय बन जाये ताकि वहां का कुछ डेवलेपमेंट हो सके। कुंडा और पूरे प्रतापगढ़ में आम भी होता है। आंवला भी होता है जबकि इलाहाबाद और कौशाम्बी में अमरूद भी होता है जिसकी जैम और जेली बनता है। हम बाहर भी भेजते हैं। इलाहाबाद में कैनी कम्पनी बनी हुई है लेकिन फूड प्रोसैसिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां चंदौली नक्सल ऐरिया और सोनभद्र का ऐरिया पूर्वांचल में आता है। मुझे याद है कि हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने चंदौली में नक्सल ऐरिया में उन्होंने अपना हैलीकाप्टर उतारा था। नक्सलाइट लीडर बासवती आयी। उसने कहा कि वह समाज की मुख्यधारा से अलग है। हमारे लिये कुछ नहीं है। वहीं श्री यादव जी ने जो घोषणा की उसके चलते वह हमारी पार्टी की कार्यकर्ता हैं। वह समाज की मुख्यधारा से जुड़ गई हैं। उसे राजनौतिक सम्मान मिला है। वहां चुनाव होता है, ग्राम प्रधान भी होता है, ब्लाक प्रमुख भी होता है। तभी हम नक्सलवाद को खत्म कर सकते हैं जब हम उन्हें शिक्षा देंगे, समाज की मुख्यधारा से उन्हें जोड़ेंगे तमाम विकास की सुविधायें देंगे तब जाकर आतंकवाद खत्म हो सकता है। अभी हमारे यहां हाई कोर्ट की बात हो रही थी। हाई कोर्ट का डिवीज़न करना चाहते हैं। जब उसकी भव्यता होती है तभी उसका अस्तित्व रखता है। आप चार, दस सुप्रीम कोर्ट कर दीजिए तो वह कोई मायने नहीं रखेगी। सुप्रीम कोर्ट के लिए लोग दिल्ली आते हैं, हर जगह सुप्रीम कोर्ट खोल दी जाए तो यह मुश्किल होगा। मैं ज्यादा कुछ न कहकर अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि ज्यादातर पूरे देश में कांग्रेस की सरकार रही है, उत्तर प्रदेश में भी ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही है। हमने विकास किए हैं, लेकिन पूर्वांचल के विकास के लिए, यहां राहुल जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ये जो तमाम 28 जिले हैं, इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मुझे विश्वास है, आप दौरा कर रहे हैं और आप इन पर विशेष ध्यान देंगे।

महोदय, जहां तक विद्युत उत्पादन की बात है। किसी एरिया में, किसी प्रदेश मे अगर बिजली न मिले तो मेरे ख्याल से वहां का विकास संभव नहीं है। आज बिजली मनुष्य की जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उससे वह रोजगार भी करता है, उससे वह व्यवसाय भी करता है। किसान बिजली से खेती करता है, सिंचाई करता है, मढ़ाई करता है, छोटे-मोटे लघु उद्योग धंधे लगाकर अपना जीवन-यापन करता है। यहां वर्तमान में 6,600 मेगावाट बिजली की बात है। वर्ष 2012 तक 12 हजार मेगावाट बिजली का लक्ष्य रखा गया है और पांच वर्ष में 32,000 मेगावाट बिजली का लक्ष्य रखा गया है। मैं चाहूंगा कि पूर्वांचल की तरफ विशेष ध्यान देकर, वहां विद्युत की जो कमी है, वहां मुश्किल से केवल 5-6 घंटे बिजली आती है उसे दूर किया जाए।

महोदय, अगर बिजली आ जाए तो मेरे ख्याल से समूचे पूर्वांचल का विकास होगा। इन्हीं बातों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

श्री दारा सिंह चौहान : महोदय, आपने मुझे इस संकल्प पर चर्चा करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आज पूर्वांचल के पिछड़ेपन और उसके लिए स्पेशल आर्थिक पैकेज की बात यहां रखी गयी है।

17.38 hrs. (Shri P.C. Chacko *in the Chair*)

महोदय, आजादी के इतने दिन बाद जब आज पूर्वांचल के पिछड़ेपन की चर्चा हो रही है तो मैं इस बात को बताना जरूरी समझता हूं कि वह पूर्वांचल की धरती, जिसने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। चाहे वह गोरखपुर का चौरी-चौरा कांड रहा हो, चाहे मऊ का मधुबन कांड रहा हो, चाहे बलिया के चित्तू पांडे रहे हों, ऐसी बहुत ही ऐतिहासिक धरती पूर्वांचल है। जहां पर पंडित राहुल सांकृत्यायन से लेकर अल्लामा सिबली नोमानी जैसे लोग पैदा हुए। वह पूर्वांचल जहां पर तमाम ऋषि, महर्षियों ने जन्म लिया और पूरे देश और दुनिया को मानवता का संदेश दिया। आज कितने दुर्भाग्य की बात है कि वह पूर्वांचल, जिसने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जहां के विद्वानों, ऋषियों, महर्षियों ने देश और दुनिया को मानवता का संदेश दिया, आज वही पूर्वांचल अपनी लाचारी और बेबसी पर रो रहा है।

महोदय, आज उसके पिछड़ेपन की चर्चा इस पार्लियामेंट में हो रही है। इस बात को मैं जरूर बताना चाहता हूं कि आज पूरे देश में जो अलग-अलग प्रदेशों की मांग हो रही है, चाहे तेलंगाना हो, चाहे हरित प्रदेश हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे बुंदेलखंड हो, इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि इस देश में जो गैर बराबरी है, जैसे परिवार है, अगर परिवार में हम एक-दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं तो भाई-भाई से अलग हो जाता है। उसे इंसाफ नहीं मिल पाता, उसे न्याय नहीं मिल पाता है। उसी तरीके से आज पूरे देश में जो अलग-अलग राज्य की मांग हो रही है, उसका एक कारण है कि जिसकी देश और प्रदेश में हुकूमत है, जिसकी गलत आर्थिक नीति के नाते जो क्षेत्र छूट गए हैं, वे अपने विकास की बात करते हैं कि हम इनसे अलग होकर अपने विकास की बात करेंगे। अपना राज्य बनाएंगे और उसके विकास की बात करेंगे। इसलिए आज अगर पूर्वांचल के पिछड़ेपन के विकास की बात हो रही है तो मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, पूर्वांचल के पिछड़ेपन के बारे में हमारे तमाम साथियों ने चर्चा की। वह प्रदेश, जिसका उत्तर प्रदेश एक हिस्सा है, जिसने एक नहीं, आधा दर्जन प्रधान मंत्री दिए, वह पूर्वांचल है। पूर्वांचल ने जय-जवान, जय किसान का नारा दिया। इस धरती पर लालबहादुर शास्त्री पैदा हुए।

सभापति महोदय, आज यहां पिछड़ेपन पर चर्चा हो रही है। लोग अपने विकास और बेहतरी के लिए तरस रहे हैं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस प्रदेश और देश में आजादी से लेकर अब तक अगर देश की सरकारों ने पिछड़ेपन की तरफ ध्यान दिया होता तो शायद आज देश की पार्लियामेंट में ऐसे क्षेत्रों के पिछड़ेपन की चर्चा नहीं होती। इस देश में आजादी मिलने के बाद भी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दास्ता एवं गुलामी थी, उसका कारण है कि आज हम अलग-अलग हिस्सों में अपनी-अपनी बात कह रहे हैं। माननीय हुक्मदेव नारायण जी कह रहे थे, उन्होंने सारी बात का निचोड़ रखा कि आज देश में हर क्षेत्र में समाज में जो असंतुलन और गैर-बराबरी है, इसका क्या कारण है?

सभापति महोदय, हम इस देश में इन्साफ, इंसानियत और मानवता की बात करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि आज देश में हम जाति के खिलाफ हैं। जाति की बुनियाद पर राजनीति करने वाले, जिसके जहन में उस क्षेत्र की गरीबी, लाचारी और बेबसी कभी दिमाग में नहीं आई। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि आज पूर्वांचल का वह गरीब, जिसे पिछड़ा कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि वहां दलित पिछड़े हों, चाहे अकलियत के लोग हों, वहां सामान्य समाज के लोग भी पिछड़े हैं, चूंकि पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। वहां के चाहे बुनकर, किसान एवं नौजवान हों, उनकी पढ़ाई-लिखाई और नौकरी का कोई साधन नहीं। मैं इसलिए इस बात को चर्चा में लाना चाहता हूं, इसकी चर्चा हो चुकी है कि आज भी प्रदेश, खास कर पूर्वांचल में रहने वाला गांव का गरीब झोंपड़ी में रहता है। आजादी के 60 साल बाद भी आज वह अपने दो जून की रोटी के लिए तरसता है। आज 60 साल के बाद भी हम पूर्वांचल के उस गरीब की चकाचौंध रोशनी में पार्लियामेंट में चर्चा करते हैं, लेकिन उस पूर्वांचल का दुर्भाग्य है कि आज भी वहां ऐसे तमाम गांव हैं - चाहे केन्द्र की सरकार कितना भी प्रचार करे, बोर्ड लगा दे, लेकिन आज भी वह गरीब बिजली के खम्भे को देखने के लिए तरस जाता है। आज भी हम पूर्वांचल के पिछड़पन की चर्चा करते हैं, जहां साढ़े छ: करोड़ लोग रहते हैं। आज भी जहां तीस फीसदी आबादी ट्रेन में बैठने के लिए तरसती है, उस पूर्वांचल की हम चर्चा करते हैं। इसका एक ही कारण है, जहां जिनकी भी सरकारें रही हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी, प्रांत से लेकर केन्द्र की सरकार में सबसे ज्यादा दिन तक रही है।

सभापति महोदय, उस समय की सरकार को पूर्वान्चल की बेहतरी और विकास के लिए जितना ध्यान देना चाहिए था, वह उसने नहीं दिया। इसी कारण आज पार्लियामेंट में पूर्वान्चल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए स्पेशल आर्थिक पैकेज की मांग हो रही है। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री, बहन मायावती जी ने ...(व्यवधान) 17 जुलाई, 2007 को पूर्वान्चल के विकास के लिए 36,270 करोड़ रुपए का एक स्पेशल पैकेज देने की मांग की, लेकिन केन्द्र सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। सड़क निर्माण हेतु 3,700 करोड़, स्वास्थ्य सुविधा विकास के लिए 2,522 करोड़, पेयजल के लिए 500 करोड़, बिजली कार्य के लिए 3,094 करोड़, सिंचाई के लिए 3,991 करोड़, गरीबों के आवास के लिए 4,112 करोड़, समाजोत्थान कार्यक्रम के लिए 8,322 करोड़, कृषि विकास के लिए 6,000 करोड़, अन्य कार्यों हेतु 2,000 करोड़ और गांव सभा की सुविधाओं के लिए 1250 करोड़ रुपए की मांग की है। पूर्वान्चल क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से स्पेशल आर्थिक पैकेज देने की मांग की थी, लेकिन केन्द्र सरकार ने उधर ध्यान नहीं दिया।

सभापति महोदय, यही नहीं, जब इस देश में राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था, जब देश की मौजूदा सरकार के पक्ष में आंकड़े नहीं थे, जब देश को जरूरत थी महिला राष्ट्रपति बनाने की, जब देश का उप राष्ट्रपति एक अल्पसंख्यक समाज से बनाने की जरूरत थी, तो हमारी नेता, उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री, बहन मायावती जी ने आगे बढ़कर केन्द्र सरकार को समर्थन दिया। इसके एवज में ...(व्यवधान) देश की सरकार और देश के प्रधान मंत्री ने केवल पूर्वान्चल नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, वहां की बिजली के लिए, जैसा हमारे मित्र ने कहा, वहां इंटरनैशनल एयरपोर्ट के लिए, बौद्ध परिपथ के विकास के लिए धन देने का वायदा किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक प्रधान मंत्री महोदय का संकल्प पूरा नहीं हो पाया है। इसी नाते आज हम सदन में इस संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं।

सभापति महोदय, आज देश में बहुत क्षेत्रीय असंतुलन है। आज भी समाज में, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आजादी मिलना चाहिए थी, वह नहीं मिली है। पूर्वान्चल के चाहे पिछड़े समाज, दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज की बात हो, बहुत पिछड़ा हुआ है। श्रीमती रत्ना सिंह जी, संकल्प पेश कर के चली गई। पूर्वान्चल का चाहे अकबरपुर हो, टांडा हो, बनारस हो या मऊ हो, तमाम क्षेत्र देश के एवरेज से बहुत पीछे हैं। इन क्षेत्रों में रहने

वाले चाहे बुनकर हों, किसान हों, नौजवान हों, उनकी बेहतरी और विकास के लिए केन्द्र सरकार को कोई टाइम-बाऊंड कार्यक्रम बनाना चाहिए था, लेकिन वह अभी तक नहीं बनाया गया है। इलाहाबाद की चर्चा हुई। वह कभी देश की जंगे आजादी का केन्द्र था और वहां से देश की आजादी की प्लानिंग होती थी और योजनाएं बनती थीं। वहां से आजादी की लड़ाई लड़ी गई, इतना ही नहीं, बल्कि आजादी के बाद, अब तक वही इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का शिक्षा का सबसे बड़ा केन्द्र रहा है, जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। फिर चाहे पूर्वान्चल का गोरखपुर इलाका हो, फिर चाहे बिहार की सीमा से लगा हुआ पडौना से लेकर राजगंज, गोरखपुर, बस्ती और बहराइच आदि जिले हैं, ये सब बहुत पीछे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि आज समाज में जो सामाजिक असंतुलन है, इन जिलों के पीछे रहने का वह भी एक बहुत बड़ा कारण है। कि आज ऐसे जो समाज के गरीब हैं, जिनको लोगों की होड़ में शामिल होने को मौका नहीं मिलता है, हम सारे लोग भी उसी में शामिल हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से जितना हो सकता है, उसने पूर्वांचल की बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम किया, चाहे गरीबों को आवास देने का सवाल हो, बुनकरों की बेहतरी के लिए काम हो। जिस गोरखपुर की चर्चा हो रही थी, वहां भी वायरल रिसर्च सैंटर की स्थापना की गई है।

इतना ही नहीं, आजादी के 60 सालों में हम महिलाओं के विकास की बात करते रहे, मैं तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी को बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए काम किया। जो गांव की गरीब बेटी है, जिसका बूढ़ा बाप मजदूरी करने के बाद अपने बच्चों को दो जून की रोटी नहीं दे सकता, अपनी बेटी को पढ़ा नहीं सकता, हमारी सरकार ने व्यवस्था की कि उसकी गरीब बेटी भी अगर कल इंटर कालेज में जायेगी, अगर फर्स्ट ईयर में एडमीशन कराएगी तो उसे एकमुश्त 15 हजार रुपये और एक साइकिल आने-जाने के लिए दी जायेगी। वह गरीब, जिसका बाप मजदूरी करने के बाद अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर सकता था, उसकी शादी नहीं कर सकता था, हमारी नेता ने उसकी शादी की पूरी व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसे तमाम जो पिछड़े समाज के लोग थे, जो गरीब हैं, जिनके पास कोई खेत नहीं, बिजनेस नहीं, नौकरी नहीं, उनके लिए भी उन्होंने काम किया। गरीबी के नाते जो लोग बड़े-बड़े महानगरों में, कोलकाता में, मुम्बई में मजदूरी करते हैं और किसी तरह से परिवार का पेट पालते हैं, उसका बेटा नहीं पढ़ सकता है, इंटर कालेज, डिग्री कालेज में पढ़ने के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश की सराकर ने उसकी जो एडमीशन फीस थी, उसकी प्रतिपूर्ति के नाम से उनको दी जा रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं, गरीब हैं, जहां लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती, लोग काम के लिए बाहर चले जाते हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने 58 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये मजदूरी कई साल पहले कर दी, अभी तो इस बजट में हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि 100 रुपया मजदूरी मैं कर रहा हूं। हमारी सरकार ने कई साल पहले यह काम कर दिया। वहां गरीबों के लिए, यह नहीं कि किसी एक समाज के लिए, हर समाज के लिए, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, बी.पी.एल. के नीचे हैं, उन सारे लोगों के लिए उन्होंने काम किया। कल जहां उनको एक कमरे का मकान मिलता था, हमारी सरकार ने...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please address the Chair. You please conclude.

श्री दारा सिंह चौहान : चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक हो, किसी भी समाज का होगा तो एक ही मानक होगा। अगर वह गरीब होगा तो उसके लिए एक लाख 75 हजार रुपये का मकान बनाकर काशीराम शहरी गरीब आवास योजना में उनकी पढ़ाई के लिए, बेहतरी के लिए गरीबों को दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, जहां तक सबसे पहले इफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, हमारी सरकार ने अपने सीमित संसाधन से कई बार केन्द्र सरकार से सवाल उठाया था, जब ऊर्जा का सवाल था कि जो डिमांड और सप्लाई गैप हमारे प्रदेश में है। इस देश की सरकार उसको समझ नहीं पा रही है, दे भी नहीं पा रही है तो अपने सीमित संसाधन से 4500 करोड़ रुपये की योजना का उत्तर प्रदेश में निर्माण हो रहा है और बिजली उत्पादन करने की दिशा में हम अग्रसर हैं, इसलिए जो पिछड़ा पूर्वांचल है, जिसके लिए हमारी माननीय सदस्या संकल्प लाई हैं,...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

श्री दारा सिंह चौहान : मैं उस पर चर्चा करते हुए इतना जरूर करना चाहूंगा कि आज पूर्वांचल, जो देश की आजादी से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा आगे रहा है, हमेशा से उसकी उपेक्षा होती रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से विकास...(व्यवधान) मैं उसकी भी बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में जो रायबरेली है, वह भी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की सीमा पर है। वहां पर तो बड़े-बड़े कल-कारखाने लग रहे हैं। वहां पर सैण्ट्रल रेलवे कोच फैक्टरी बन रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टैक्नोलोजी की शाखा खुल रही है, नेशनल ऑटोमोबाइल टैस्टिंग एंड रिसर्च इफ्रास्ट्रक्चर का कारखाना खुल रहा है। मैं चाहता हूं कि...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt him.

â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : इंट्रप्ट मत करिए। आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : मैं उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी को बधाई दूंगा, जिस बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया, जिस बाबा साहब ने इस देश में रहने वाले गरीबों, लाचारों और मजलूमों को आवाज दी, स्वाभिमान-सम्मान से जिंदगी जीने का अधिकार दिया, अगर उनके नाम पर कोई स्मारक बनाया जा रहा है, तो वह गलत नहीं है, सही है। तमाम ऐसे महापुरूषों के नाम पर हमने काम किया है।

सभापति महोदय, जिस तरीके से देश के दूसरे हिस्सों का विकास हुआ, पूर्वांचल का भी विकास उसी प्रकार से हो। पूर्वांचल में एम्स की तर्ज पर बड़े-बड़े हास्पिटल्स खोले जाने चाहिए। वहां पढ़ाई के लिए मेडिकल-टेक्निकल एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां की सड़कों के विकास के लिए 5,900 करोड़ रूपए का जो प्रपोजल प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए हमारी प्रदेश सरकार ने भेजा है, मैं चाहता हूं कि उसे जल्दी से जल्दी स्वीकृत करके और स्पेशल आर्थिक पैकेज देकर वहां के लोगों को, दूसरे जो विकसित प्रदेश हैं, उनके साथ खड़ा करने के लिए पूरा-पूरा सहयोग करना चाहिए। मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए।

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में जिनकी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 6 करोड़ 54 लाख आबादी है, उसके विकास से संबंधित जो संकल्प का प्रस्ताव श्रीमती रत्ना सिंह जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि 27 जनपदों में फैले इस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान दशा है, उसका आकलन उत्तर प्रदेश सरकार ने करा रखा है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराये गए आकलन से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 36 संकेतकों के आधार पर कराये गए विकास के कंपोजिट इंडेक्स की सूची से जो आकलन किया गया है, उसके अनुसार प्रथम श्रेणी में विकास संबंधी 125 एवं इससे अधिक अंक पाये हुए जो वेरी हाई कंपोजिट इंडेक्स आफ डेवलपमेंट के कुल छः जिले उत्तर प्रदेश में हैं, उसमें से पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई जिला नहीं है। इसके पश्चात् द्वितीय श्रेणी में 110 से 125 अंक पाए हुए हाइली कंपोजिट इंडेक्स आफ डेवलपमेंट वाले सात जिले उत्तर प्रदेश में हैं, जिसमें से पूर्वी उत्तर प्रदेश का मात्र एक जिला वाराणसी है। तृतीय श्रेणी में 95 से 110 अंक के बीच मीडियम कंपोजिट इंडेक्स आफ डेवलपमेंट में 24 जनपद उत्तर प्रदेश के हैं, जिसमें से मात्र पांच जनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं।

माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही कराए गए इस सर्वेक्षण के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के 80 से 95 अंक प्राप्त लो कंपोजिट इंडेक्स आफ डेवलपमेंट के 18 जनपदों में से 8 जनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। इसी के साथ पांचवीं श्रेणी में वेरी लो कंपोजिट इंडेक्स आफ डेवलपमेंट में, ऐसे जिले जिनके 80 अंक से भी कम हैं, उत्तर प्रदेश में मात्र 16 जनपद उत्तर प्रदेश में हैं, जिसमें से 12 जनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का नक्शा है। हम यहां पर राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठकर अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की चर्चा करते तो अच्छा था। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो बद् से बद्तर स्थिति है, पिछले बीस सालों में उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने शासन किया, वह इसके लिए कम दोषी नहीं हैं। वर्ष 1994 में जो सरकार थी, उसने पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो रीढ़ थी, जो चीनी मिलें थीं, उनको बेचने का प्रयास किया। आज वर्ष 2009 में जो सरकार है, वह गन्ने का भाव नहीं तय कर पा रही है। उसकी अपनी चीनी मिलें, सरकार की चीनी मिलें, ...(व्यवधान) आप सुनने को तैयार होइए, उसकी अपनी 22 चीनी मिलें, एक भी सरकार नहीं चला रही है, न चलाने का उसका इरादा है। उस गन्ने को निजी चीनी मिलों के हाथ में देकर भ्रष्टाचार से पैसा कमाने का आज उत्तर प्रदेश सरकार काम करने जा रही है। उसके पास चलाने के लिए 22 चीनी मिलें हैं, लेकिन उसमें से एक भी चीनी मिल नहीं चलायी जाती है।

18.00 hrs.

आजादी के बाद आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेल से छितौनी और बगहा जुड़ा। उत्तर बिहार सीधे दिल्ली से जुड़ गया, लेकिन आनंदनगर से लेकर गोंडा तक आमान परिवर्तन का काम अधूरा पड़ा हुआ है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Harsh Vardhanji, please take your seat. You can continue your speech when the House takes up this discussion next day.

SHRI HARSH VARDHAN : Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN : Some hon. Members are waiting to raise some submissions. I hope the House will agree for extending the time until we complete these submissions.

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes.

MR. CHAIRMAN : Thank you. We will now take up 'Zero hour' submissions.